



देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 05

अंक - 55

जौनपुर, शनिवार, 10 अक्टूबर 2026

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें

विरोध प्रदर्शन से पहले जंतर-मंतर पर कड़ा सुरक्षा पहरा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोंकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शन से पहले शनिवार को नयी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान लाउडस्पीकों से चेतावनी दी जा रही है, प्रमुख चौराहों पर अवरोधक लगाए गए हैं और जंतर-मंतर पर हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। पटेल चौक गोल चक्कर पर पुलिस की भारी मौजूदगी देखी गई। हरी और खाकी रंग की वर्दी पहने अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवान भारी बैग, सुरक्षा उपकरण और राइफल लेकर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च करते हुए संसद मार्ग थाने के पास एकत्र हुए। यह थाना जंतर-मंतर से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। जंतर-मंतर के आसपास की सड़कें संसद मार्ग और अशोक रोड पर पुलिस की गतिविधियां तेज थीं। वहां मीडिया की गाड़ियां भी खड़ी थीं। पिछले प्रदर्शन के दौरान ज्यादाती करने के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली पुलिस के कई जवानों ने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे। सुरक्षाकर्मियों को लाने वाली बसें थाने के पास सड़क किनारे खड़ी थीं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात दिल्ली पुलिस की 'पिक फोर्स' को भी कई जगहों पर तैनात किया गया था। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिसकर्मी लाठियां और सुखसा उपकरण लेकर तैनात दिखाई दिए।

कॉजपा प्रदर्शन से पहले दिल्ली में 25,000 जवान तैनात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में जंतर-मंतर पर कोंकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लगभग 25,000 जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन पर प्रवेश और निकास को लेकर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं दिए जाने के बाद सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रस्तावित प्रदर्शन के संबंध में संगठन से प्राप्त पत्र केवल एक सूचना मात्र था, न कि अनुमति मांगने के लिए नियमानुसार जमा किया गया आवेदन। बड़े पैमाने पर लोगों के जुटने की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर एकत्र होने से रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर में निगरानी बढ़ा दी है। सुरक्षा व्यवस्था सभालने में दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 120 से अधिक कंपनियां तैनात की जा सकती हैं।

महिला और बाल विकास पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का समापन, पीएम मोदी बोले- आंगनवाड़ी बने सामुदायिक भागीदारी का केंद्र

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में महिला और बाल विकास पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की सोच के तहत आयोजित की जा रही विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का हिस्सा था। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में पोषण और बचपन के देखभाल, बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण और बेहतर तालमेल से सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी



ने चर्चा की सराहना करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर फैसले लेने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य जिला स्तर और नगर पालिका व महानगर पालिका स्तर पर भी इसी तरह के 'चिंतन शिविर' आयोजित कर इस

मॉडल को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी विशेष चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि वे जमीनी स्तर के अपने अनुभव और व्यावहारिक समाधान साझा कर सकें। प्रधानमंत्री ने 'जन भागीदारी' पर जोर

यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर भाजपा के आठ और सपा के दो उम्मीदवार जीते

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए सियासी तस्वीर साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आठ और समाजवादी पार्टी (सपा) के दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच में दो निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्वे खारिज होने और नाम वापसी की समयसीमा तक किसी अन्य प्रत्याशी के मैदान में नहीं रहने से सभी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही 16 अक्टूबर को प्रस्तावित मतदान की आवश्यकता समाप्त हो गई और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो गया। भाजपा की ओर से राज्यसभा पहुंचने वालों में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह, भाजपा के प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश पाल, श्रुति गंगवार, विद्यासागर सोनकर, प्रियंका सिंह रावत, राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडेय और राम प्रताप सिंह चौहान शामिल हैं। वहीं, सपा के वरिष्ठ नेता एवं



राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी ने उच्च सदन में जगह बनाई है। निर्वाचन अधिकारी अजीत कुमार वर्मा ने शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिकताएं पूरी करते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रमाणपत्र जारी किए।

दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन पर बोले शिवराज सिंह चौहान, विदेशी ताकतों से मिलकर अराजकता फैला रहा विपक्ष

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 अक्टूबर को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हालिया उपचुनाव जीतों की तारीफ की। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि चुनाव में हारने के बाद वे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रच रही हैं। चौहान ने कहा कि वोटरो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के लिए अपना समर्थन फिर से जताया है। उन्होंने कहा कि कल हुए उपचुनावों में, चाहे बंगाल हो, असम हो या पुडुचेरी, भाजपा और ने शानदार जीत हासिल की। जनता का फैसला साफ है। लोग कह रहे हैं कि हमारा संकल्प एक विकसित भारत बनाना है और हम इसे पूरा करेंगे। हम इसे

हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे लगातार संवैधानिक संस्थाओं



को कमजोर करने और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ, जनता विकास और विकसित भारत के निर्माण के

लिए पीएम मोदी के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ, विपक्ष निराश और हताश है। वे चुनावी मैदान में जीत नहीं सकते और न ही जनता का भरोसा

जीत सकते हैं। नतीजतन, वे सड़कों पर अराजकता फैलाने, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने, लोकतंत्र में विश्वास को खत्म करने की साजिश

देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र को केवल एक संस्थान के रूप में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी के आसपास रहने वाले परिवारों को विशेष अवसरों पर बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, खेलौने और स्थानीय स्तर पर उपयोगी चीजें देकर योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। पीएम मोदी ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आसपास के आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद ले सकते हैं और सामाजिक प्रभाव से जुड़े अध्ययन कर सकते हैं।

अपने आस-पड़ोस और उससे बाहरी क्षेत्र के घटनाक्रम पर भारत की लगातार नजर - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत अपने क्षेत्र और उससे बाहर हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहा है और उनके रणनीतिक प्रभावों का आकलन कर रहा है क्योंकि दुनिया आधुनिक युद्ध एवं वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। रक्षा मंत्री ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' के तहत हवाई प्रदर्शन देखने के बाद अपने संबोधन में कहा, "भारत अपने क्षेत्र और उससे बाहर हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहा है तथा उनके रणनीतिक प्रभावों का भी आकलन कर रहा है।" उन्होंने कहा कि स्थापित वैश्विक व्यवस्था तेजी से बदल रही है और भविष्य

की व्यवस्था कैसी होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के

मतलब दुनिया से अलग-थलग रहना नहीं है। इसका अर्थ महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और



दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारतीय सशस्त्र बलों की संरचना, संसाधनों और रणनीति में बुनियादी बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का

विकास के साथ-साथ उनके निर्माण, रखरखाव और उन्नयन की घरेलू क्षमता विकसित करना है।" रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय सैन्य

अभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' के तहत भारतीय वायुसेना के हवाई प्रदर्शन को देखा। उन्होंने वायुसेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लड़ाकू विमानों को अलग-अलग 'फार्मेशन' में उड़ान भरते और हवाई करतब दिखाते देखा। यह अभ्यास 26 सितंबर से शुरू हुआ था जो कि 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायु सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण, अभियानगत अनुभवों के आदान-प्रदान और एक-दूसरे की कार्यप्रणाली को समझने के माध्यम से भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर बनाना है।

नवरात्रि और दशहरा को लेकर डीएम-एसएसपी ने रुदौली क्षेत्र में किया निरीक्षण

(डॉक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।आगामी नवरात्रि, दुर्गापूजा एवं दशहरा पर्व के मद्देनजर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने शनिवार को रुदौली सर्किल के प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ग्रामीण राधेश्याम राय और क्षेत्राधिकारी रुदौली अरविंद सोनकर भी मौजूद रहे।इन अधिकारियों ने मां कामाख्या धाम घाट, रेछ घाट



सहित प्रमुख स्थलों का जायजा लेकर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुदामा चरित से दिया सच्ची मितता और समर्पण का सदेश, पांच सतों के सान्निध्य में भक्तिमय हुआ नोएडा श्रीमद्भागवत कथा के सातवें दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, शुक्रदेव विदाई प्रसंग ने भावविभोर किए भक्त

ब्यूरो चीफ/ सत्य प्रकाश उपाध्याय

नोएडा। सेक्टर-33 स्थित शिल्प हाट के निकट हेलीपैड ग्राउंड में भारत विकास परिषद, नोएडा की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के सातवें दिन शुक्रवार को श्री सुदामा चरित्र और शुक्रदेव विदाई के भावपूर्ण प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कथा व्यास आचार्य मृदुल कांत शास्त्री जी महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की निस्वार्थ मित्रता का वर्णन करते हुए प्रेम, विश्वास, समर्पण और भक्ति का संदेश दिया। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे

और भक्ति व आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण पांच पूज्य सतों का पावन सान्निध्य रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज तथा वृंदावन के श्री सुदामा कुटी महाराज सहित सतों के दर्शन और आशीर्वाचन प्राप्त कर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। कथा व्यास आचार्य मृदुल कांत शास्त्री जी महाराज ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि सच्ची मित्रता में पद, प्रतिष्ठा और धन का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण ही सबसे

बड़ी पूंजी हैं। भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता समाज को समानता, आत्मीयता और निस्वार्थ प्रेम की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा मनुष्य को सदाचार, सेवा, विनम्रता और संस्कारों से युक्त जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। शुक्रदेव विदाई के प्रसंग के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के महत्व से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि कथा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, पार्किंग, सुरक्षा और स्वच्छता की समुचित व्यवस्था

रहे। सरयू प्रसाद यादव, एसपीओ कुशीनगर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। डॉ. कृष्ण गोपाल जी के साथ मनोज गुप्ता, राजीव त्यागी और नरेश शर्मा सहित विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने कथा व्यास का माल्यार्पण कर एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। कथा के मुख्य यजमान डॉ. वी.के. गुप्ता और श्रीमती रीना गुप्ता रहे।

भारत विकास परिषद, नोएडा के अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि कथा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, पार्किंग, सुरक्षा और स्वच्छता की समुचित व्यवस्था



की गई है। कथा के उपरांत प्रतिदिन भंडारे और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर परिषद के सचिव अखिलेश भदौरिया, कोषाध्यक्ष अक्षय



अग्रवाल, विनय शर्मा, अजय सरिना, एन. गोविल, प्रताप मेहता, विपिन मल्हन, केशव गंगल, एन.के. अग्रवाल, रामरतन शर्मा, राकेश कत्याल, डॉ. नरेश शर्मा, मनोज बंसल, संगीता सैनी, विकास

सुरेन्द्र गर्ग, राजेंद्र गर्ग और मुकुल वाजपेयी सहित परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

संपादकीय

अब नई बेंच बनेगी

केंद्र ने विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, तो उसके बाद लगभग तीन साल गुजर चुके हैं। अब नई बेंच बनेगी, तो जैसा तजुर्बा है, उसका फैसला आने में अभी कई और वर्ष गुजरेंगे। मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय की। पांच जजों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि ये नियुक्तियां तीन सदस्यीय समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश, एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल रहेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार को यह निर्णय पसंद नहीं आया, तो उसने उसी वर्ष दिसंबर में संसद से विधेयक पारित करवा कर समिति की संरचना बदल दी। इसके तहत प्रावधान किया गया कि नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री, और नेता विपक्ष रहेंगे। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो न्यायालय ने वह याचिका दो जजों की बेंच को सौंप दी। उस पीठ का बंटा हुआ फैसला बु्गवार को आया। एक जज— न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने याचिका में पेश दलील को जायज मानते हुए कहा कि उपरोक्त कानून ने नियुक्ति समिति में सत्ता पक्ष का बहुमत कायम कर दिया है, जिससे वहां नेता विपक्ष की मौजूदगी सजावटी बन भर रह गई है। वे इस तर्क से भी सहमत हुए कि मौजूदा स्वरूप में समिति श्वत्तंत्र्य मालूम नहीं पड़ती। लेकिन दूसरे जज जस्टिस एस.सी. शर्मा ने सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश दलील से सहमति जताई कि इस मामले से महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न जुड़े हुए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की अधिक बड़ी बेंच ही फैसला दे सकती है। तो अब मामला फिर से प्रधान न्यायाधीश के पास चला गया है। वे तय करेंगे कि क्या इस मुद्दे पर फिर से संविधान पीठ बने? केंद्र ने जब विधायी पहल के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, तो उसके बाद लगभग तीन साल गुजर चुके हैं। अब नई बेंच बनेगी, तो जैसा तजुर्बा है, उसका फैसला आने में अभी कई और वर्ष गुजरेंगे। इस बीच तमाम चुनाव सरकार के मन—माफिक बने निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते रहेंगे। अतरु सामान्य स्थितियों में फैसले का इंतजार असहनीय महसूस नहीं होता। लेकिन निर्वाचन आयोग जैसी शिकायतों से धिक्ता चला गया है, उसको लेकर जैसे संदेह सार्वजनिक दायरे में मौजूद हैं, उन्हें देखते हुए बहुत बड़े जनमत को संभावित देर अंधेर का कारण बनती मालूम पड़ेगी।

सामूहिक भागीदारी से विकसित भारत का संकल्प होगा पूरा, बनेगा स्वर्णिम भारत

ओम प्रकाश डहरिया

सेवा जब संकल्प बनती है, संकल्प जब समर्पण में बदलता है और समर्पण जब राष्ट्र निर्माण का आधार बनता है, तब एक ऐसी यात्रा प्रारंभ होती है, जो केवल किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे देश की आकांक्षाओं और भविष्य की यात्रा बन जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने का अवसर इसी भाव को अभिव्यक्त करता है। जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए तय की गई इस यात्रा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने तथा विकसित भारत के संकल्प को जन—जन से जोड़ने के उद्देश्य से देशभर में श्सेवा संकल्प अभियानच चलाया जा रहा है। इसी अभियान की एक प्रेरक पहल श्सेवा ज्योति कलश यात्राच है। जो गांव, जिला और राज्य स्तर पर सेवा, समर्पण, निष्ठा और राष्ट्र संकल्प की भावना को आगे बढ़ा रही है।

7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शासन की जिम्मेदारी संभाली थी। वहां से प्रारंभ हुई उनकी शासन और जनसेवा की यात्रा ने 7 अक्टूबर 2026 को 25 वर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा किया है। इन ढाई दशकों में शासन के केंद्र में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग को रखते हुए विकास को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास प्रमुखता से सामने आया है। प्रधानमंत्री के रूप में श्शबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयासच का मंत्र इसी सोच को व्यापक स्वरूप देता है। आज विकसित भारत—2047 का संकल्प इसी जनभागीदारी को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानकर आगे बढ़ने का आह्वान करता है।

श्शेवा ज्योति कलश यात्राच अपने आप में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभावना का सुंदर संगम है। ज्योति हमारी परंपरा में प्रकाश, ज्ञान, आशा और सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक है, जबकि कलश मंगल तथा पवित्रता और शुभ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। जब यही ज्योति और कलश सेवा के भाव से जुड़ते हैं, तब वे राष्ट्र निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का संदेश देते हैं। यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ प्रत्येक नागरिक को यह स्मरण कराने का अवसर भी है कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय का साझा संकल्प है। भारत जब वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तब हमारा देश कैसा होगा, इसका निर्धारण आज लिए जा रहे संकल्पों और किए जा रहे प्रयासों से होगा। विकसित भारत का अर्थ केवल बड़ी अर्थव्यवस्था, आधुनिक शहर, बेहतर सड़कें, उद्योग अथवा अत्याधुनिक तकनीक तक सीमित नहीं है। विकसित भारत वह होगा, जहां किसान समृद्ध हो, महिलाएं आत्मनिर्भर हों, युवाओं के सपनों को अवसर मिले, गरीबों को आगे बढ़ने की शक्ति मिले, बच्चों को बेहतर शिक्षा और पोषण मिले तथा समाज का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा में सम्मान के साथ सहभागी बने। यही कारण है कि सेवा संकल्प अभियान का वास्तविक महत्व जनभागीदारी में निहित है। गांव से शहर तक जब नागरिक सेवा के किसी छोटे से कार्य को भी अपने कर्तव्य से जोड़ते हैं, तो वही छोटा प्रयास राष्ट्र निर्माण की बड़ी शक्ति बन जाता है। स्वच्छता के लिए श्रमदान, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण, जरूरतमंदों की सहायता, रक्तदान, जल संरक्षण, बेटियों की शिक्षा, माताओं और बच्चों के सुपोषण के लिए जागरूकता अथवा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देनाकृ ऐसे अनेक कार्य विकसित भारत की बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं। राष्ट्र की प्रगति केवल नीतियों से नहीं, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदार भागीदारी से गति प्राप्त करती है। श्शेवा ज्योति कलश यात्राच इसी चेतना को गांव—गांव और जन—जन तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है। यह यात्रा हमें बताती है कि सेवा किसी पद की मोहताज नहीं होती। समाज का प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता के अनुरूप सेवा कर सकता है। किसान खेत में उत्पादन बढ़ाकर, शिक्षक बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर, युवा नवभार और उद्यमिता के माध्यम से, महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर और आम नागरिक अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे सार्थक माध्यम यही हो सकता है कि सेवा के भाव को केवल एक आयोजन तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे जीवन का संस्कार बनाया जाए। सेवा संकल्प अभियान हमें अतीत की यात्रा का स्मरण कराने के साथ भविष्य की जिम्मेदारी भी सौंपता है। यह कृतज्ञता के साथ कर्तव्य का, उपलब्धियों के साथ आकांक्षाओं का और सेवा के साथ राष्ट्र संकल्प का अभियान है। आज जब भारत आत्मविश्वास के साथ वर्ष 2047 की ओर आगे बढ़ रहा है, तब सेवा की वह ज्योति हर गांव, हर घर और हर मन में प्रज्वलित होना आवश्यक है। करोड़ों नागरिकों के छोटे—छोटे प्रयास जब एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य से जुड़ेंगे, तभी विकसित भारत का विराट संकल्प साकार होगा। आएं, सेवा को संस्कार, समर्पण को शक्ति और राष्ट्रहित को सर्वोच्च कर्तव्य मानकर आगे बढ़ें।

विचार

ट्रंप प्रशासन को करारा जवाब देकर भारत ने लूटी दुनिया की वाहवाही

नीरज
अमेरिका में भारतीय प्रतिभा का लोहा मानने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अब उसी प्रतिभा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसने अमेरिकी तकनीकी उद्योग को वैश्विक ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। एक तरफ ट्रंप भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला की तारीफ करते हैं, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जेडी वांस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट समेत आठ प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों को ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया से जुड़े च्छद कार्यक्रम से निर्लंबित कर देता है। इस फैसले से हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों के भविष्य और अमेरिका में स्थायी निवास पाने की उम्मीदों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि, भारत सरकार ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में स्पष्ट किया है कि च्छद कार्यक्रम और एच—1बी वीजा अलग—अलग व्यवस्थाएं हैं तथा च्छद आवेदनों पर रोक लगने से मौजूदा एच—1बी वीजा या उनके धारकों और बिगैरों की स्थिति अपने आप प्रभावित नहीं होती, भले ही पात्र कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी दोदूक कहा है कि प्रतिभाओं की आवाजाही भारत और अमेरिका, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद है। इससे अमेरिकी कंपनियों को उच्च



गोपाल
सर्वोच्च न्यायालय अब उस स्थिति में है जहां से वे जवाब सबसे विश्वसनीय रूप से सामने आ सकते हैं। जरूरी बात यह नहीं है कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष से बचाया जाए, बल्कि यह है कि मतदाता सूची को लेकर होने वाले विवाद को इस बात के झगड़े में बदलने से रोका जाए कि क्या लोकतांत्रिक रेफरी पर अब भी भरोसा किया जा सकता है?रत की चुनाव प्रणाली अब ऐसी स्थिति में पहुंच गयी है जहां बहस सिर्फमतदाता सूची में गलतियों तक सीमित नहीं है। ज्यादा अहम सवाल यह है कि क्या नागरिक उस संवैधानिक संस्था पर भरोसा बनाए रख सकते हैं, जिसे यह तय करना है कि जिम्मेदारी दी गई है कि सूची में कौन शामिल होगा, नाम कैसे हटाए

राजेश
नक्शे देखें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रुख को देखते हुए उम्मीद बंधती है कि देश की सर्वोच्च अदालत करोड़ों मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगी। उसके कोर्ट के भीतर से जाहिर की गई भावनाओं और जनमत के बड़े हिस्से के मिजाज को समझने की अपेक्षा है। सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के तौर—तरीकों का विरोध कर रही हैं। निश्चित तौर पर वे जनमत के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार हर किसी के निशाने पर हैं। उन्हें हटाने की मांग और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया रह करने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से याचिका दायर की गई है। उनके कोर्ट की खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा कराने के लिए मजबूर करने वाली कॉंकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बहस में सुप्रीम कोर्ट के

कौशल वाले पेशेवर, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता

और रोजगार सृजन में मदद मिलती है। मंत्रालय ने वांस की उन टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई है, जिनमें विदेशी कर्मचारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। भारत ने कहा कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित और कुशल योगदानकर्ता हैं तथा उन्हें औपनिवेशिक इतिहास की पीड़ादायक याद दिलाने वाली भाषा से संबोधित करना गहरे तौर पर आपत्तिजनक है। देखा जाये तो भारत का यह बयान महज औपचारिक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि वाशिंगटन के लिए स्पष्ट संदेश है कि भारतीय प्रतिभा को अपमानित करके और उसके अवसर सीमित करके दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप प्रशासन का यह कदम अमेरिकी रोजगार की सुखा तक सीमित है या इसके पीछे चुनावी राजनीति, भारत पर आर्थिक दबाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों के समीकरण भी काम कर रहे हैं? उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति आश्रितों की स्थिति अपने आप प्रभावित नहीं होती, भले ही पात्र कर्मचारियों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी दोदूक कहा है कि प्रतिभाओं की आवाजाही भारत और अमेरिका, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद है। इससे अमेरिकी कंपनियों को उच्च

टेक्नोलॉजीज, कॉग्निजेंट और कैंपजेमिनी शामिल हैं। प्रशासन का आरोप है कि कुछ कंपनियों ने विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए ऐसी व्यवस्था का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिकी कामगारों के रोजगार और वेतन पर प्रतिकूल असर पड़ा। अब सवाल उठता है कि आखिर है क्या और इस पर रोक से भारतीयों को कितना नुकसान होगा? रोजगार आ्ारित ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। सामान्यत: नियोक्ता को अमेरिकी श्रम विभाग से प्रमाणित कराना होता है कि संबंधित पद के लिए पर्याप्त इच्छुक और योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं और विदेशी कर्मचारी की नियुक्ति से अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन तथा कामकाजी परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद ही नियोक्ता विदेशी कर्मचारी के रोजगार आधारित स्थायी निवास की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। इस कार्यक्रम से आठ कंपनियों को बाहर करने का मतलब यह है कि वे नई च्छद अर्जियां दाखिल नहीं कर पाएंगी और उनकी लंबित अर्जियां पर भी प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इन कंपनियों में काम कर रहे सभी भारतीयों के एच—1बी वीजा रद्द हो गए हैं या उन्हें तत्काल अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। असली खतरा उन कर्मचारियों के लिए है जो छह साल की सामान्य एच—1बी अवधि के करीब पहुंच रहे हैं और अमेरिका में

जानता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध उपाय अपनाए गए, और क्या आयोग के फैसले एक बहु—सदस्यीय संवैधानिक संस्था के लिए जरूरी सामूहिक प्रक्रिया के जरिए—लिए गए श्रेय थे?एसआईआर के साथ—साथ एक और अनुसुलझा संस्थागत मुद्दा भी चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने गत सितंबर माह में बंटा हुआ फैसला सुनया था कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामलों को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। उस कानून ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े घटनाक्रमों ने इस विवाद को महज एक आम पक्षपाती शिकायत मानकर खारिज करना मुश्किल बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मई में फैसला किया था कि चुनाव आयोग के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बिहार में एसआईआर करने का अधिकार है। इसलिए, यह फैसला इस बात का समर्थन नहीं करता कि एसआईआर अपने आप में असंवैधानिक है। लेकिन असली मुद्दा अब इस बात पर आ गया है कि उस अधि

भारत का चुनावी संकट अब ले रहा सर्वोच्च न्यायालय की परीक्षा

ाकार का इस्तेमाल कैसे किया गया, नाम हटाने को लेकर क्या सुरक्षा उपाय अपनाए गए, और क्या आयोग के फैसले एक बहु—सदस्यीय संवैधानिक संस्था के लिए जरूरी सामूहिक प्रक्रिया के जरिए—लिए गए श्रेय थे?एसआईआर के साथ—साथ एक और अनुसुलझा संस्थागत मुद्दा भी चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने गत सितंबर माह में बंटा हुआ फैसला सुनया था कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामलों को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। उस कानून ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े घटनाक्रमों ने इस विवाद को महज एक आम पक्षपाती शिकायत मानकर खारिज करना मुश्किल बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मई में फैसला किया था कि चुनाव आयोग के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बिहार में एसआईआर करने का अधिकार है। इसलिए, यह फैसला इस बात का समर्थन नहीं करता कि एसआईआर अपने आप में असंवैधानिक है। लेकिन असली मुद्दा अब इस बात पर आ गया है कि उस अधि

वोटर के अधिकार की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी

न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायमूर्ति, चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त और विधि विशेषज्ञ आगे आए हैं।केवल सत्ताधारी विशेषज्ञ जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ खड़ी है। उसके पास आयोग के बचाव में ठोस और कारगर दलीलें नहीं हैं। फिर भी, उसके कोर्ट प्रवक्ता सक्रिय रहते हैं। समझ से परे है कि चुनाव आयुक्त पर संदेह जताने और सवाल उठाने का बचाव भाजपा की तरफ से क्यों होता है। भाजपा का बचाव चुनाव आयोग की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। संदेह पैदा होता है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहा है। वैसे भी, सरकार ने आयोग को अपनी शर्तों पर चलाने और मनमानी आयुक्त मानमूली बात नहीं है। इससे किए हैं। चुनाव आयोग द्वारा संविधान और कानून की मंशा के खिलाफ काम करने का मामला इतना जोर नहीं पकड़ता यदि दो चुनाव आयुक्तों से बीएस संघू और विवेक जोशी की आपत्तियों का इंडियन एक्सप्रेस की खबर में खुलासा नहीं होता। दोनों आयुक्तों ने दस माह में 14 बार मुख्य कार्गन के लिए मजबूर करने वाली कॉंकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बहस में सुप्रीम कोर्ट के



लंबे समय तक बने रहने के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर निर्भर हैं। कुछ परिस्थितियों में ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया के निर्धारित चरण पूरे होने पर एच—1बी अवधि बढ़ाई जा सकती है। च्छद प्रक्रिया रुकने से ऐसे कर्मचारियों के लिए भविष्य की योजना बनाना कहीं अधिक मुश्किल हो सकता है। देखा जाये तो अमेरिकी प्रशासन की इस करारवाई ने भारतीय आईटी उद्योग से लेकर अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं तक अनिश्चितता बढ़ा दी है। जेडी हमला करते हुए आरोप लगाया कि कंपनी ने 2025 में करीब 6,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की, लेकिन साथ ही 6,000 से अधिक एच—1बी वीजा की मंजूरी हासिल की और 3,600 से अधिक च्छद आवेदन भी दाखिल किए। उन्होंने विदेशी कर्मचारियों को शर्फीन इंडेवर्ड सर्टैडस और ऐसी कंपनियों को श्वीजा मिल्सस्

तक कह दिया। श्रम सचिव सॉन्डरलिंग का दावा है कि केवल इन कंपनियों ने 2009 से लगभग 30 लाख विदेशी कर्मचारियों के लिए अनुरोध किए, 2.30 लाख से अधिक एच—1बी वीजा मंजूर कराए और एक लाख से अधिक च्छद प्रमाणन हासिल किए। प्रशासन इन आंकड़ों को अमेरिकी कामगारों के अवसर छिनने से जोड़ रहा है। लेकिन आवेदन, मंजूरी, वास्तविक नियुक्ति और अमेरिकी कर्मचारी की जगह विदेशी कर्मचारी रखे जाने के आंकड़े अलग—अलग हैं। माइक्रोसॉफ्ट का पक्ष भी इस बहस में महत्वपूर्ण है। कंपनी ने कहा है कि उसके करीब 6,000 एच—1बी आवेदनों में लगभग 80 प्रतिशत मौजूदा कर्मचारियों के वीजा विस्तार या उनकी स्थिति बदलने से संबंधित थे। इसका अर्थ है कि सभी आवेदनों को नई विदेशी भर्तियों के रूप में नहीं देखा जा सकता। साथ ही नेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर सॉफ्टवेयर इं

न्यायालय की परीक्षा

से बचा सकता है और उल्लंघन साबित होने पर उपाय बता सकता है। इनमें से किसी के लिए भी न्यायालय को संविधान को फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उन परिस्थितियों में न्यायिक प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया और आगे और लामबंदी की घोषणा की गई है। चुनाव आयोग उन आरोपों को खारिज करता है कि उसके कार्यों का उद्देश्य सत्ताधारी भाजपा को लाभ पहुंचाना था, जबकि प्रदर्शनकारी और विपक्षी दल ठीक ऐसे ही पक्षपाती परिणामों का आरोप लगाते हैं। उन विरोध प्रदर्शनों के आरोपों के सुबूत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। न ही जन आक्रोश को संवैधानिक फैसले का विकल्प माना जाना चाहिए। उनका महत्व कहीं और रेरू वे दिखाते हैं कि क्या होता है जब प्रशासनिक प्रक्रिया पर बहस लोकतांत्रिक वैधता के विवाद में बदल जाती है। संवैधानिक प्रणाली में अभी भी ऐसे रास्ते हैं जिन्हसे विवाद को सुलझाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड मांग सकता है, जांच कर सकता है कि क्या कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, आयोग के भीतर असहमति के कानूनी महत्व को नि्धरित कर सकता है, पात्र मतदाताओं को गलत तरीके से बाहर किए जाने

न्यायालय की परीक्षा

हैं। वैसे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने किसी का नाम लिए बिना कहा है किश् सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या किसी अन्य कोर्ट के जज या रिटायर्ड जज को उन मामलों में नहीं बोलना चाहिए जो किसी कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं। करते हुए अपने सहयोगी जज के कथन पर गौर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने जस्टिस भुयन की बात को अन्य आगे बढ़ाया है। उन्होंने एक अन्य व्याख्यान में कहा कि आपके पास ऐसा चुनाव आयोग नहीं हो सकता जो इस तरह काम करे या जिसका कामकाज इतना खराब हो। वे सवाल उठाते हैं, मतदाताओं को इतने बड़े पैमाने पर बाहर करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई। पश्चिम बंगाल चुनावों में 90 लाख वोटों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यह हैरान करने वाला आंकड़ा है। वे जोर देते हैं, 90 लाख वोटों का मताधिकार से वंचित होना भी सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगाने के लिए प्रेरित नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व और एक वर्तमान न्यायाधीश की चिंता चुनाव आयोग की कार्यशैली के खिलाफ व्याप्त बैचौनी और अस्तौष की झलक दिखाती

टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के संस्थापक राजीव दामाडकर की व्याख्या इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने लाती है। उनके मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन अब केवल यह नहीं पूछ रहा कि विदेशी कर्मचारी योग्य है या नहीं, बल्कि यह भी जांच रहा है कि विदेशी श्रम की भर्ती, भुगतान और आपूर्ति का कारोबारी मॉडल किस तरह काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी तकनीकी पद के लिए अमेरिकी कंपनी एक लाख पचास हजार डॉलर खर्च करती है और कोई मध्यस्थ विदेशी कर्मचारी को उसकी वास्तविक आर्थिक कीमत से काफी कम भुगतान करके अंतर अपने मुनाफे के रूप में रखता है, तो सवाल भारतीय कर्मचारी बनाम अमेरिकी कर्मचारी का नहीं, बल्कि पारदर्शी वेतन बनाम श्रम लागत के अनुचित लाभ का बनता है। यह जांच का वैध विषय हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सभी भारतीय पेशेवरों को संदेह के घेरे में रखने के लिए नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने सत्य नडेला की तारीफ क्यों की और वांस ने माइक्रोसॉफ्ट पर इतना सख्त रुख क्यों अपनाया? इसका उत्तर अमेरिकी राजनीति की दो प्राथमिकताओं में है। प्रंप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और तकनीकी निवेश में अमेरिकी नेतृत्व मजबूत करना है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण है।

न्यायालय की परीक्षा

लेकिन मौजूदा टकराव में छिपी चेतावनी को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। चुनावी लोकतंत्र आखिरकार कानूनों, मशीनों या मतदाता डेटाबेसों की तुलना में अर्धिक नाजुक चीज पर टिका होता है। यह इस विश्वास पर टिका होता है कि हारने वाले को लगता है कि मुकाबला ईमानदारी से आयोजित किया गया था और मतदाता को लगता है कि भाग लेने का अधिकार किसी अपारदर्शी प्रक्रिया से गायब नहीं हो सकता। वह भरोसा अब असामान्य दबाव में है। इसे बहाल करने के लिए चुनौती का सामना कर रही संस्था के आश्वासनों और उसके राजनीतिक विरोधियों के आरोपों से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए स्वतंत्र जांच में टिकने वाली तथ्यों और राजनीतिक विभाजन के पर अधिकार रखने वाले संवैधानिक जवाबों की आवश्यकता है।सर्वोच्च न्यायालय अब उस स्थिति में है जहां से वे जवाब सबसे विश्वसनीय रूप से सामने आ सकते हैं। जरूरी बात यह नहीं है कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष से बचाया जाए, बल्कि यह है कि मतदाता सूची को लेकर होने वाले विवाद को इस बात के झगड़े में बदलने से रोका जाए कि क्या लोकतांत्रिक रेफरी पर अब भी भरोसा किया जा सकता है?

न्यायालय की परीक्षा

मीडियाश् के स्वर फिलहाल थोड़े मंद पड़े हैं। बहरहाल, मताधिकार के मूल मुद्दे पर लौटते हैं। चुनाव आयोग का मूल काम स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और वोटरों का अधिकार सुनिश्चित करना रहा है। इधर, वह अपनी मूल भूमिका से भटक कर वोटरों को निकालने की मुहिम में लगा है। एसआईआर में लोगों के सामने कदम—कदम पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। नए वोटरों का पंजीयन करने वाले फार्म 6 में पूछा गया कि क्या वे, उनके माता—पिता, दादा—दादी 2002 की पिछली एसआईआर के समय मतदाता सूचियों में शामिल थे। यह अनिवार्य शर्त कितनी कठिन है। सवाल है, कितने वोटर ऐसी शर्त पूरी कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रुकावटों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने आयोग के हर फैसले पर मुहर लगाई। चुनाव आयोग का एक कह रहा है कि उसने फार्म—6 में कोई बदलाव नहीं किए हैं। सिर्फ एक घोषणा जोड़ी है। उसे भी हटा लिया है। आयोग कोई भी सफाई दे किसी तरह की अतिरिक्त घोषणा को बदलाव ही कहेंगे। फार्म—6 में केवल सरकार बदलाव कर सकती है। फिर आयोग ने ऐसा क्यों किया है। दरअसल, उसे पूरा यकीन है कि वह कुछ भी करे ।

नवरात्रि के पहले दिन 31 पंडालों में खुलेंगे मां के कपाट, जिले में 2700 स्थानों पर स्थापित होंगी प्रतिमाएं



अयोध्या [शारदीय नौरात्रि रविवार से शुरू हो रहा है।शहरी क्षेत्र में नवरात्र के पहले दिन 31 दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलेंगे।वहीं, पूरे जिले में करीब 2700 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी।जबकि शेष दुर्गा पूजा प्रतिमाओं की स्थापना 16 अक्टूबर को होगी।यह जानकारी शनिवार को शहर की आभा होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय दुर्गा पूजा एवं रामलीला समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने दी।उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर की रात दुर्गा प्रतिमाएं जीआईसी मैदान पर जीआईसी मैदान में एकत्र होगी और 20 अक्टूबर को विसर्जन शोभा

सपा ने सादगीपूर्ण ढंग से मनाई मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि, दी श्रद्धांजलि

जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी, नेताजी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान



जौनपुर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शनिवार को जौनपुर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अ्ध यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सपाजनों ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन, समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय के लिए किए गए कार्यों को

याद किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपना पूरा जीवन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों, अधिवक्ताओं और व्यापारियों के हक एवं अधिकारों की लड़ाई लड़ने में समर्पित किया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान और अर्ध ाकार दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नेताजी के विचारों और समाजवादी सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूर्व विधायक राजनरायन बिंद, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ.

के पदाधिकारी तथा पुलिस कर्मियों को दें जिससे उन पर उचित कार्यवाही किया जा सके। विसर्जन को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष निर्मली कुंड घाट पर अधिक पानी है इसलिए विसर्जन करते समय किसी कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा और पिछले घाटों की अपेक्षा इस बार बड़ा घाट भी बनाया गया है।पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि इस समय सबसे बड़ी समस्या नाका से चौक के बीच सड़क की है।मालूम हो कि दुर्गा पूजा पर्व के दौरान खासकर अंतिम तीन दिन दूर-दराज से आने वाले संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चों सहित अन्य श्रद्धालु माता रानी का दर्शन करने आते हैं और इस बार इस मार्ग पर सिविल लाइन डालने की नाम पर संबंधित विभाग द्वारा सड़क को खुद डाला गया है जिस पर श्रद्धालुओं को गुजरते समय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा इसकी शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है तो उन्होंने इसे दूर करने का समय मांगा है। इस मौके पर उनके अलावा समित के संरक्षक विजय गुप्ता, गगन जायसवाल, अरुण अग्रवाल,प्रेमनाथ राय, केशव बिगुलर, तारकेश्वर शर्मा पंकज, सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

अवधनाथ पाल, दीपचंद राम, जयहिंद यादव, हीरालाल विश्वकर्मा, श्यामबहादुर पाल, राजेंद्र यादव टाड़गर, गामा सोनकर, अनवारूल हक गुड्डू, शर्मिला रमेश, विकास यादव, अजय रंजन यादव, जगदीश प्रसाद मौर्य गप्पू, दिलीप प्रजापति, गुड्डू सोनकर, अशोक यादव नायक, रामजतन यादव, वीरेंद्र यादव, निजामुद्दीन अंसारी, रामू मौर्य, पवन मंडल, रवि यादव, अजहर रहमान, साजिद अलीम और रुखसार अहमद सहित अन्य नेताओं ने भी विचार व्यक्त किए तथा नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सभा की जिलाध्यक्ष शर्मिला रमेश ने उन्हें मनोनयन पत्र सौंपकर शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में राजेश विश्वकर्मा, सुशील श्रीवास्तव, गुलाब यादव शीठी, कमलेश यादव, दीपक विश्वकर्मा, डॉ. शबनम नाज, साहबलाल गौतम, हरिश्चंद्र प्रभाकर, कमाल आजमी और राजेश यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी ने संयुक्तरूप से रामलीला स्थल का किया निरीक्षण,दिये आवश्यक निर्देश

अयोध्या। शुक्रवार को देर शाम दुर्गापूजा एवं दशहरा पर्व को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट संजीव उपाध्याय,सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज कुमार शर्मा ने नगर क्षेत्र के छह रामलीला स्थलों का निरीक्षण किया।इस दौरान बाल रामलीला कमेटी कोठा पार्च, टकसाल रामलीला कमेटी चौक, हैदरगंज, साहिबगंज, देवकाली और फतेहगंज रामलीला स्थलों का जायजा लिया गया।निरीक्षण के दौरान रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों को पर्याप्त विद्युत प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आग लगने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए बालू और पानी की व्यवस्था रखने को कहा गया,ताकि आग पर शुरुआती स्तर पर ही काबू पाया जा सके।अधि कारियों ने कमेटियों को स्वयंसेवकों की तैनाती कर उन्हें पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए, जिससे

सुरक्षा ब्यवस्था का जायजा लिया।उन्होंने अग्निशमन कर्मियों के साथ चौक के अलावा नाका, रिकाबगंज, फतेहगंज, सुभाषनगर, खवासपुरा, शांति चौक, मकबरा,रीडगंज, दिल्ली दरवाजा, नियांवा, कसाबबाडा, देवकाली, अश्विनीपुरम कॉलोनी, वजीरगंज जप्ती, साहबगंज,कोठा पार्चा सहित कई रामलीला स्थलों व दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया।उन्होंने रामलीला व दुर्गा पूजा समिति पदाधि कारियों को अग्निशमन विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप पंडाल निर्माण कराने तथा आग से बचाव के आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है।ऐसे में पंडालों में अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए,ताकि किसी

सीएफओ ने कई रामलीला व दुर्गा पूजा स्थलों का निरीक्षण कर पदाधिकारियों को दिये निर्देश

अयोध्या। दुर्गा पूजा तथा रामलीला को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीएफओ एमपी सिंह ने शुक्रवार देर शाम व शनिवार को चौक सहित शहर के प्रमुख दुर्गा पूजा तथा रामलीला स्थल पर जाकर पंडालों का निरीक्षण किया।इस मौके पर उन्होंने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।उन्होंने अग्निशमन कर्मियों के साथ चौक के अलावा नाका, रिकाबगंज, फतेहगंज, सुभाषनगर, खवासपुरा, शांति चौक, मकबरा,रीडगंज, दिल्ली दरवाजा, नियांवा, कसाबबाडा, देवकाली, अश्विनीपुरम कॉलोनी, वजीरगंज जप्ती, साहबगंज,कोठा पार्चा सहित कई रामलीला स्थलों व दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया।उन्होंने रामलीला व दुर्गा पूजा समिति पदाधि कारियों को अग्निशमन विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप पंडाल निर्माण कराने तथा आग से बचाव के आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है।ऐसे में पंडालों में अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए,ताकि किसी

अब्न दान महादान अजय अंबष्ट अपर जिलाधिकारी

1। नवम्बर को भगवान चित्रगुप्त शोभायात्रा –सरस चन्द श्रीवास्तव



ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। अन्न दान महादान है उक्त विचार आज राष्ट्रीय कायस्थ महारिषद जौनपुर द्वारा आयोजित पितरों की याद में आयोजित भोजन वितरण कार्यक्रम में शामिल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला अधिकारी जौनपुर अजय अंबष्ट जी ,(सी आर ओ) ने कहा और कहा कि पूर्वजों के याद में समाज के हर तबका को भोजन पैकेट वितरण से समाजिक समरसता होती हैं और भूखे को अन्न प्यासे को पानी दान से कोई बड़ा दान नहीं हैं। श्री चित्रगुप्त भगवान पूजन महासमिति जौनपुर के संयोजक सरस चन्द श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि भगवान



पुलिस को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिल सके। मौके पर मौजूद चौकी प्रभारियों और नोडल पुलिसकर्मियों को रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखने तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी ने रामलीला तथा दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारियों से अपील

किया कि वे रामलीला तथा दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल के आसपास संदिग्ध ास्तुओं के साथ-साथ अराजकता फैलाने वाले लोगों पर भी नजर रखें और कुछ भी संदिग्ध दिखाई देने तथा अराजकता फैलाने वाले लोगों पर आशंका हो तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय दुर्गा पूजा के पदाधिकारी को भी दें जिस समय रहते उन पर कार्यवाही की जा सके।



भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।अग्निशमन विभाग ने आयोजकों

से सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं में लापरवाही न बरतने की अपील की।

प्रमुख रूप से राजेश श्रीवास्तव बच्चा भईया ,डॉ सलिल श्रीवास्तव , राजीव श्रीवास्तव रोशन जी, लखन श्रीवास्तव,डॉ गणतंत्र श्रीवास्तव,गौरव श्रीवास्तव,संदीप श्रीवास्तव,मनीष श्रीवास्तव पत्रकार,मनीष श्रीवास्तव बच्चा,धनंजय श्रीवास्तव राजन श्रीवास्तव,राजेश किशोर श्रीवास्तव राजू, विनीत श्रीवास्तव,आलोक बृजेश वर्मा,सोमेश श्रीवास्तव,अश्विनी अस्थाना, अभिलव श्रीवास्तव,लालबहादुर यादव नेपाली सभासद,विजय कुमार श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव,अमित श्रीवास्तव,अनूप श्रीवास्तव,सुधाकर श्रीवास्तव राजीव श्रीवास्तव, सुमति श्रीवास्तव,देवेंद्र श्रीवास्तव ,अवनीश श्रीवास्तव दीपक,प्रमोद श्रीवास्तव,दिनेश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार विश्व प्रकाश श्रीवास्तव दीपक ,अंकित श्रीवास्तव पत्रकार, मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट,अजय श्रीवास्तव अज्यू, राजीव कुमार,मंगल श्रीवास्तव , राहुल श्रीवास्तव,दीपू श्रीवास्तव सिपाह,अनिल बबलू श्रीवास्तव,अनिल श्रीवास्तव,शैलेन्द्र मोहन, आर पी श्रीवास्तव,कमलेश निषाद,अतुल मिश्रा,गौतम यादव,अनूप यादव का कार्यक्रम सफलता पूर्वक होने में विशेष योगदान रहा।

नाका–मकबरा–सुभाषनगर–चौक मार्ग की हालत खराब

अयोध्या।रामनगरी में एक ओर शनिवार शाम से रामलीला का मंचन शुरू हो गया है,वहीं रविवार से शहर के 31 स्थानों पर दुर्गा पूजा की शुरुआत होने जा रही है।धार्मिक आयोजनों को लेकर शहर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने के बीच नाका से मकबरा,सुभाषनगर होते हुए चौक तक जाने वाले संपर्क मार्ग की बद्दहाल स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।सड़क पर जगह–जगह गहरे गड्ढे होने से स्थानीय लोगों के साथ ही रामलीला और दुर्गा पूजा देखने आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक,सीवर लाइन बिछाने के कार्य के बाद सड़क की स्थिति खराब हुई है।उनका कहना है कि मार्ग पर कई स्थानों पर बड़े–बड़े गड्ढे बने हुए हैं,जिससे आवागमन में दिक्कत होती है।ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर समस्या और गंभीर हो सकती है।नाका–मकबरा–सुभाषनगर–चौक मार्ग शहर के प्रमुख संपर्क मार्गों में शामिल है।दुर्गा पूजा के अंतिम तीन दिनों में इस मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने की संभावना है।केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और संख्या लाखों तक पहुंच सकती है।ऐसे में सड़क पर बने गड्ढे यातायात के साथ-साथ पैदल आने–जाने वाले लोगों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकते हैं।महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ सकती है।केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों ने भी इस समस्या को लेकर शिकायत किए जाने की बात कही है। हालांकि,उनके मुताबिक,अब तक सड़क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आया है।

साइबर अपराध से मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान में सभागार में शनिवार को डिजिटल युग में साइबर अपराधों का मनोवैज्ञानिक प्रभावरू रोकथाम, जागरूकता एवं सहायता' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग, वेलनेस सेंटर एवं साइबर क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में साइबर अपराधों, डिजिटल उत्पीड़न और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इन अपराधों का लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में किसी परिचित चेहरे या जानी–पहचानी आवाज को देखकर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। साइबर अपराधी किसी विद्यार्थी की फीस, किसी की जीवनभर की बचत और किसी बुजुर्ग की पूरी कमाई तक हड़प ले रहे हैं। ऐसे में जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है।कुलपति ने कहा कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम स्वयं साइबर अपराधों से सुरक्षित रहें और अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरूक एवं सुरक्षित रखें, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ–साथ मानसिक तनाव और यंत्रणा से भी बचाया जा सके।मुख्य अतिथि एवं प्रख्यात साइबर क्राइम विशेषज्ञ डॉ. अनुप गिरधर ने कहा कि साइबर ठगी, ऑनलाइन उत्पीड़न और भ्रामक सूचनाओं के कारण लोग तनाव, डर और मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल दुनिया में भ्रामक सूचनाओं और वीडियो के जरिए लोगों की सोचने–समझने और सही–गलत का फैसला करने की क्षमता को भी प्रभावित किया जा रहा है। इसे एक तरह से 'ब्रेन हैकिंग' कहा जा सकता है।

छात्राओं की सिखाए तनाव प्रबंधन के प्रभावी तरीके

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में तनाव प्रबंध ान एवं उससे निपटने की प्रभावी रणनीतियों पर महिला छात्रावास में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह के दिशा–निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावासों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. विनोद कुमार वर्मा ने छात्राओं को तनाव के कारणों, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व तथा दैनिक जीवन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने तनावपूर्ण परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और सकारात्मक सोच अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। यावहारिक मनोविज्ञान विभाग के अ्ध यक्ष एवं वेलनेस सेंटर के संयोजक प्रो. अजय प्रताप सिंह ने कहा कि मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ जीवन के लिए दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और तनाव प्रबंधन की समझ बेहद जरूरी है।कार्यक्रम का संयोजन व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग की सहायक आचार्य एवं अतिरिक्त मुख्य वार्डन महिला डॉ. अन्नू त्यागी ने किया।

एमएलसी चुनाव के लिए मतदान का प्रशिक्षण

जौनपुर। वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी निर्वाचन को निष्पक्ष एवं सुचारु ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी सैमुअल पाल एन की उपस्थिति में आयोजित प्रशिक्षण में प्रथम मतदान अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान संबंधी दायित्वों तथा निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों की जानकारी दी गई।जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रशिक्षण में दी गई जानकारी का भली–भांति अध्ययन कर लें और निर्वाचन प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न कराएं।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा, मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह, परियोजना निदेशक के.के. पांडेय, जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी सहित ।

साम्न्ध हिन्दी दैनिक	देश की उपासना
स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित। सम्पादक श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मो0 – 7007415808, 9415034002 Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com	समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।